पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 18, अंक 1/2017

सड़क सुरक्षा कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना आवश्यक!

राजस्थान में सड़क सुरक्षा के लिए अच्छे कानून तो है, लेकिन उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करवाने की जरूरत है। इसके साथ ही प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं की भी कमी है, जिससे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पाती इससे मृत्यु दर बढ़ रही है।

डॉ. बी.एल. सोनी, अतिरिक्त पुलिस महा-निदेशक, राजस्थान डिजास्टर एक्शन फोर्स ने 'कट्स' द्वारा 30 मार्च 2017 को 'मोटर वाहन (संशोधन) बिल 2016' पर आयोजित पैरवी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने राजस्थान में अधिक से अधिक ट्रोमा सेंटर स्थापित करने की जरूरत जताई और जी.पी.एस. जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करने पर बल दिया।

उद्घाटन सत्र में सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत के सड़क सुरक्षा परिदृश्य को प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रतिदिन 407 लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जिसमें 43.7 प्रतिशत मौतें तेज गति से व अतिभारित वाहन चलाने के कारण होती हैं।

जॉर्ज चेरियन, निदेशक, 'कट्स' इंटरनेशनल ने अपने प्रारंभिक संबोधन में बताया कि पूरे विश्व में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत दुर्घटनाएं भारत में होती है। भारतीय सड़कों पर हर घंटे 57 दुर्घटनाएं होती है, जिनमें 15 लोग अपनी जिन्दगी खो देते हैं।

तकनीकी सत्र में डॉ. माया टंडन, सी.ई.ओ., सहायता संस्था; यतेन्द्र कुमार गुप्ता, विधि विशेषज्ञ व अनिल जैन, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, राजस्थान ने सड़क सुरक्षा से संबंधित अपने विचारों एवं अनुभवों से प्रतिभागियों को अवगत कराया और हाल ही उनके द्वारा संस्था एवं राज्य सरकार के स्तर पर उठाए गए कदमों की जानकारी दी। राजीव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मानव तस्करी), राजस्थान ने भी इस अवसर पर राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित अपने अनुभवों को साझा किया।

मोटर वाहन संशोधन बिल 2016 के बारे में चर्चा करते हुए 'कट्स' प्रतिनिधि मधुसूदन शर्मा ने कहा कि तेजी से वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, सीट बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग नहीं करना एवं बाल सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली में कमी सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारक है। मोटर वाहन अधिनियम में अभी तक 89 संशोधन हो चुके हैं। इस अवसर पर सड़क दुर्घटना पीड़ित डॉ. वर्षा प्रधान एवं लक्ष्मीकांत शर्मा ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए प्रतिभागियों से निवेदन किया कि वे भी लोगों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाने को प्रेरित करें।

दीपक सक्सेना, सहायक निदेशक, 'कट्स' ने प्रतिभागियों और अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि 'कट्स' पिछले दो दशकों से भी ज्यादा समय से सड़क सुरक्षा मुद्दों पर काम करता रहा है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर बल दिया।

बैठक में उपभोक्ता कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों, परिवहन विभाग के अधिकारियों, यातायात पुलिस और अन्य हितधारकों सहित 70 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी सक्रिय भागीदारी दी।

इस अंक में...

- बूंद-बूंद सिंचाई में हो गया बड़ा 'लीकेज' 3
- भारत में पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट 5
- अफसरशाही होगी ज्यादा जवाबदेह 7
- नहीं हो रहा विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग! . 8
- अब पानी भी हो जाएगा महंगा 9

जरूरी है उत्पादनकर्ताओं और उपभोक्ताओं में जैविक खेती के प्रति जागरूकता!

राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष प्रो. सांवरलाल जाट ने कहा है कि जैविक उत्पाद की मांग तेजी से बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर भी उपभोक्ता जैविक उत्पादों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन किसान और उपभोक्ता जैविक और अजैविक खाद्य पदार्थों का आसानी से पता नहीं लगा सकते। क्योंकि, जैविक से जुड़ी जानकारी उनके पास नहीं है। इसके लिए किसानों और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए।

प्रो. जाट ने 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा जयपुर में 23 फरवरी 2017 को आयोजित जैविक उत्पादन मेले में किसानों, उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों व अन्य संभागियों को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि राजस्थान में करीब एक लाख 56 हजार हैक्टर में जैविक खेती हो रही है। इसके लिए पिछले 4-5 सालों से किसानों में आकर्षण बढ़ा है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार होगा और उत्पादन में तेजी से इजाफा होगा।

जॉर्ज चेरियन, निदेशक 'कट्स' ने कार्यक्रम के प्रारंभ में जैविक खेती के आंकड़ों के माध्यम से देश-विदेश के स्तर पर कई तथ्य प्रस्तुत किए और कहा कि 'कट्स' द्वारा जैविक खेती के प्रति किसानों और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 'नियाम' की निदेशक डॉ. हेमा यादव ने जैविक उत्पाद विपणन पर जानकारी दी। दीपक सक्सेना, सहायक निदेशक 'कट्स' ने प्रो-ऑर्गेनिक परियोजना के तहत की गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला और भविष्य की रूपरेखा के बारे में स्लाइड शो के माध्यम से विस्तार से बताया।

इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज के प्रो. मोहन कुमार एस. ने जैविक खेती के आर्थिक पहलुओं के बारे में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया। राजस्थान गौ सेवा के अध्यक्ष जे.एस.भंडारी ने जैविक खाद की महत्ता पर प्रकाश डाला। मेले में स्थानीय किसानों ने 19 स्टालों पर उनके द्वारा उत्पादित जैविक फल, सब्जियों एवं अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया, जिसका प्रो.जाट ने अवलोकन किया। मेले में जयपुर जिले के कई उपभोक्ताओं ने जैविक वस्तुओं की खरीददारी भी की।

कार्यक्रम के प्रारंभ में परियोजना अधिकारी राजदीप पारीक ने सभी आगन्तुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में 100 से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

प्रशासन की सक्रियता और नागरिकों के सहयोग से हैदराबाद शहर नगरीय विकास में अग्रणी

हैदराबाद नगर निगम का बजट करीब 5 हजार करोड़ रुपए सालाना है। इसकी कुल कमाई में 45 फीसदी हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। एक हजार करोड़ रुपए अन्य करों से प्राप्त होता है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की सालाना कमाई विज्ञापन से होती है। खास बात यह है कि हैदराबाद की जनता स्वेच्छा से नगरीय कर जमा कराती है।

'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा राजस्थान के महापौरों के सिटी मेयर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित हैदराबाद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान यह उभर कर सामने आया। हैदराबाद में निकलने वाले करीब 5 हजार टन कचरे से कम्पोज व आरडीएफ बनाने के बाद सीमेंट फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है। वहां नगर निगम के सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं।

सभी कामों का मॉनिटरिंग सिस्टम काफी मजबूत है। सीवरेज का गंदा पानी रिचार्ज करके उपचारित किया जाता है, जिसका उपयोग प्लांटेशन में हो रहा है। निगम के 150 वार्डो को 25 हजार कर्मचारी साफ सुथरा रखते हैं। कचरा संग्रहण के लिए पूरे शहर में 1800 टैक्सियां लगी हुई है।

भ्रमण के दौरान जोधपुर के महापौर घनश्याम ओझा, भरतपुर के महापौर शिवसिंह भोट, उप महापौर इन्द्रजीत सिंह, जयपुर के उप महापौर मनोज भारद्वाज, अजमेर के उप महापौर सम्पत सांखला एवं 'कट्स' निदेशक जॉर्ज चेरियन के साथ अमरदीप सिंह, मधुसूदन शर्मा, सत्यपाल सिंह और स्वायत शासन विभाग के ओमप्रकाश काला ने हैदराबाद नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर चर्चा की और अपने अनुभवों को साझा किया।

बूंद-बूंद सिंचाई में हो गया बड़ा 'लीकेज'

प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में बड़ा लीकेज सामने आया है। उद्यान विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर किसानों को मिलने वाली रकम डीलर और कंपनियां हड़प गई। प्रदेश के चालीस स्थानों पर कराई गई जांच में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है।

ऐसे हुआ सब्सिडी में फर्जीवाड़ा

कुछ रकम देने के बाद किसानों को झांसा दे एनओसी ली गई। उसके आधार पर सब्सिडी डीलरों के खातों में पहुंची। काम पूरा हुआ या नहीं इसका सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारी करते हैं। मिलीभगत से काम पूरे हुए बिना सब्सिडी जारी हुई।

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने अब तीन साल में बांटी गई करीब 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी के सभी मामलों की जांच कराने का निर्णय किया है। बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत उद्यान विभाग की ओर से 50 से 70 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को दी जाती है। विभाग की ओर से अधिकृत डीलर किसानों के बताए स्थान पर संसाधन लगाता है। काम पूरा होने पर किसानों से एनओसी मिलने पर विभाग सब्सिडी की रकम डीलर को देता है। मामले में लिप्त पाए गए राम किशोर मीणा, सहायक निदेशक (उद्यान) सहित अधिकारी के.के. वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। *(रा.प., 23.02.17, 24.02.17)*

हर महीने 30 लाख का गलत भुगतान

चिकित्सा विभाग में चहेतों को फायदा पहुंचाने का सिलसिला जारी है। एसएमएस अस्पताल में एक फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए सारे नियम कायदों को दरकिनार कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन छह महीनों से अधिक समय तक ऐसी फर्म को 30 लाख रुपए का हर महीने भुगतान करता रहा है, जिसने कभी आवेदन ही नहीं किया। अभी भी इस फर्म को 30 लाख रुपए हर महीने भुगतान किया जा रहा है।

मामले के अनुसार अस्पताल में कम्प्यूटर मेन पावर के लिए 2016 में आवेदन किए गए थे। इसमें अस्पताल ने नियमानुसार ऐसेन्ट कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी फर्म को ठेका दे दिया। लेकिन इस फर्म ने कुछ ही समय बाद एक इसी ऐसेन्ट नाम से दूसरी फर्म बना ली। जबकि इस फर्म के पेन कार्ड और सर्विस टैक्स नम्बर मूल फर्म से अलग थे। *(दै.भा., 30.01.17)*

गाज-पट्टी सप्लाई में धांधली

घाव भरने वाली गाज-बैंडेज निर्माता फर्में बाहर से सस्ते दामों पर गाज-बैंडेज खरीदकर सिर्फ लेबल लगाकर सरकार को सप्लाई कर रही है। यह खुलासा औषधि नियंत्रण संगठन की ओर से जयपुर, कोटा और राजसमंद की 14 फर्मों में जांच के बाद सामने आया है।

बुनकर संघ व नेशनल हैंडलूम द्वारा बुनकर सोसायटियों से हर साल करीबन 25 करोड़ रुपए की गाज-बैंडेज खरीदी जाती है। यह फर्में मेरठ से सस्ते में गाज-बैंडेज खरीदती है और अपना लेबल लगाकर सरकार को महंगे दामों में बेच देती है। इन गाज-बैंडेज की क्वालिटी सही नहीं होने से घाव भरने में 10 से 25 दिन ज्यादा लगते हैं और संक्रमण की संभावना भी रहती है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। *(दै.भा., 29.03.17)*

करोड़पति 'माननीय' बने निर्धन

सांसदों और विधायकों के रसूख और उनकी धन-दौलत का सच किसी से छुपा नहीं, लेकिन एक डेटा एनालिसिस साइट ने जब देश भर के 4910 में से 4848 सांसद-विधायकों के आयकर रिटर्न का अध्ययन किया तो अलग कहानी सामने आई। इनमें से 1141 यानी 24 प्रतिशत सांसदों व विधायकों ने दो दावे किए। पहला उन्हें किसान होने या पूर्वोत्तर राज्यों से होने के नाते आयकर में छूट है। दूसरा उनकी किसी तरह की और आय नहीं होती।

मतलब यह कि हर चौथा माननीय आयकर टैक्स से छूट ले रहा है। वहीं 35 प्रतिशत ने अपनी सालाना आय 2.5 लाख से कम घोषित की है और 40 प्रतिशत ने 2.5 लाख से 10 लाख रुपए होने का दावा किया है। जबकि चुनावों में आधे से ज्यादा सासंदों व विधायकों ने अपनी संपत्ति दो करोड़ से ज्यादा घोषित की है। *(रा.प., 17.02.17)*

स्किल डवलपमेंट में हड़पे करोड़ों

पन्द्रह लाख युवाओं को स्वरोजगार देने की वसुंधरा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को अफसरों ने फेल करने में कसर नहीं छोड़ी। युवाओं को स्किल्ड करने के नाम पर न सिर्फ फर्जी ट्रेनिंग सेंटर दिखाए गए, बल्कि इन सेंटरों पर फर्जी ऐंट्री दिखाकर लाखों रुपए का भुगतान उठाया गया।

इसका खुलासा महालेखाकार की गोपनीय जांच रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी की टीम ने मार्च 2016 से जुलाई 2016 के बीच जयपुर, अलवर और कोटा में संचालित 18 स्किल डवलपमेंट सेंटर्स में जांच की तो यह घोटाला सामने आया। इसके अलावा चूरू, हनुमानगढ़, नागौर व चित्तौड़गढ़ में भी गड़बड़ी सामने आई है। अब इन सात जिलों के 27 सेंटर्स को बन्द करने का फैसला लिया गया है।

(दै.भा., 04.03.17, 19.03.17)

टैंकर भेजे कम, दिखाए ज्यादा

जलदाय विभाग में पेयजल आपूर्ति के लिए भेजे गए टैंकरों की संख्या में काफी गड़बड़ियां सामने आई है। मामला वर्ष 2013-14 में जयपुर स्थित बस्सी सहित 215 गांवों में जलापूर्ति से जुड़ा है। इसे लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम (एसीबी) जब बस्सी में एसडीएम, तहसीलदार और जलदाय विभाग के कार्यालयों में जांच के लिए पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया।

एसीबी ने इन कार्यालयों से पेयजल सप्लाई के टैंकरों से जुड़े दस्तावेज जुटाए। जब रिकॉर्ड को खंगाला गया तो सामने आया कि ठेकेदार ने गांवों में पानी के टैंकर तो कम भेजे लेकिन भुगतान ज्यादा टैंकरों का उठाया। कई जगह तो रिकॉर्ड ही नहीं मिला। इस खेल में सामने आया है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया है। *(रा.प., 24.02.17)*

बिना मापदण्ड बना दी सड़कें

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने 28 जिलों में करीब 300 सड़क बिना पात्र बस्तियों में बना दी। इसके कारण केंद्र ने भी करीब 26.22 करोड़ रुपए की अनुदान राशि की कटौती कर दी। यही नहीं योजना के तहत स्वीकृत आंकड़ों को ऑनलाइन भी अपडेट कर दिया गया।

प्रधानमंत्री योजना के अभिलेखों की जांच में सीएजी ने पाया कि पीडब्लूडी ने राष्ट्रीय ग्राम सड़क विकास एजेंसी को भेजे गए 28 जिलों की 301 सड़क से बिना जुड़ी बस्तियों को सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार नहीं थे। अर्थात इन बस्तियों की आबादी 500 से कम होने के कारण पात्र नहीं थी। *(दै.न., 24.03.17)*

निशुल्क दवा में की कटौती

सरकार ने निशुल्क दवा योजना के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में 280 करोड़ रुपए देने की घोषणा के बावजूद साल पूरा होने से पहले ही 70 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। दूसरी ओर पिछले एक माह में आवश्यक दवाओं के क्रय आदेश ही जारी नहीं हुए। मरीजों को तीन से चार माह तक कई आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।

हालांकि योजना में 30 नई दवाएं और शामिल की गई है। सरकार का कहना है कि निशुल्क दवा योजना के बजट में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। कमी होगी तो हम और बजट देने का प्रयास करेंगे। मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। *(दै.भा., 20.01.17)*

'निगरानी' पर लेटलतीफ सरकार

प्रदेश भर की पंचायतीराज को मिलने वाले करीब 7 हजार करोड़ रुपए के अनुदान और बजट की निगरानी पर राज्य सरकार की लेटलतीफी सामने आ रही है। मामला विभाग के नए एकीकृत राज ई-पंचायत सॉफ्टवेयर से जुड़ा है, जिसके जरिए पंचायतों में विकास कार्य, लागत और अन्य सम्पूर्ण जानकारी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होनी है ।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा की थी। लेकिन पूरा वित्तीय वर्ष गुजरने के बावजूद विभाग इसे लागू नहीं कर पाया। एक साल लेटलतीफी में गुजारने के बाद अब सरकार इसे आनन-फानन में लागू करने की तैयारी में है, जो इतना जल्द संभव नहीं हो सकता।

(रा.प., 27.03.17)

दस माह में महज 30 फीसदी खर्च

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष की राशि दस महीने बाद आधी भी खर्च नहीं होने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग पर दबाव बढ़ने लगा है। विभाग को अब 31 मार्च तक 80 फीसदी राशि खर्च करके दिखानी है। ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग ने हाल ही में जिलों में राशि खर्च नहीं होने पर राज्य स्तरीय विशेष दलों को समीक्षा के लिए भेजा था।

दलों की समीक्षा में सभी जिलों में औसतन खर्च की बेहद खराब रिपोर्ट सामने आई। ज्यादातर जिलों में नकद शेष के अलावा कई मदों में राशि उपलब्ध होने के बावजूद भी पैसा समय पर खर्च नहीं किया गया। विभाग ने खर्च के लिए अब टारगेट तय कर दिए हैं लेकिन अभी भी पालना मुश्किल दिख रही है। *(दै.न., 18.02.17)*

फर्जीवाड़ा रोकने में ही हुआ फर्जीवाड़ा

सरकार ने 26 हजार राशन दुकानों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भले ही माइक्रो एटीएम मशीन सप्लाई कर दी है, लेकिन मशीन सप्लाई करने वाली कंपनी ने फर्जीवाड़ा कर सरकार को चपत लगा दी है। जोधपुर की मैसर्स प्रसाइस ऑटोमेशन एंड रोबोटिक फर्म ने फर्जी दस्तावेज बना कर मशीन सप्लाई करने के लिए 24.50 करोड़ रुपए का टेंडर ले लिया।

अधिकारियों ने फर्म को 8.50 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। जबकि फर्म ने दो जिलों में करीब 6 लाख रुपए की घटिया मशीन सप्लाई कर दी जो अभी भी एक्टिव नहीं हुई है। मामला खुला तो विभाग के अधिकारी अब खुद को बचाने में लगे हैं।
(दै.भा., 14.02.17)

ऐसे डूब रहा है राजस्थान रोडवेज

राजस्थान रोडवेज में टिकट बिक्री को लेकर भारी गड़बड़ियां हुई हैं, जिससे निगम को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इसका खुलासा विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक रोडवेज ने 2014 से 2016 के बीच महिला यात्रियों के टिकट में 30 प्रतिशत रियायती कोटे में 55 लाख से ज्यादा पुरुषों ने यात्रा की। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के करीब साढे सात लाख टिकट उन यात्रियों को जारी किए जो 20 से 59 साल के थे। इनमें करीब 13.14 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। *(दै.भा., 29.03.17)*

मनरेगा का ढोल... पोल ही पोल

प्रदेश में मनरेगा का ढिंढोरा तो खूब पीटा जाता है लेकिन हकीकत कुछ और है। केन्द्र व राज्य सरकार योजना के तहत सिर्फ बजट बढ़ा कर भले ही खुश हो रही है, पर

जरूरतमंदों को रोजगार देने पर ध्यान ही नहीं है। ऐसे में इस साल प्रदेश की कुल 9894 में से 2352 ग्राम पंचायतों में एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। यानी इस महीने तक इन पंचायतों में किसी को भी योजना का लाभ नहीं मिला है। जबकि मौजूदा वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज दो माह बचे हैं।

राज्य सरकार मान रही है कि इस बार पैसा ज्यादा दिया गया है, लेकिन रोजगार के मामले में पिछड़ गए है। अब जिला कलेक्टरों को इस पर फोकस करने को कहा गया है। राजेन्द्र राठौड़, ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज मंत्री का कहना है कि कुछ पंचायतें ऐसी रह गई है जहां रोजगार का नियोजन शून्य है, अब उन पर खास ध्यान दिया जाएगा। *(रा.प., 20.02.17)*

भारत में पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट

भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। सर्वे में शामिल 85 फीसदी भारतीयों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट माना है। इन लोगों ने कहा है कि पुलिस में कुछ अथवा सभी भ्रष्ट हैं।

इसके बाद 84 फीसदी लोगों ने अन्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों को भ्रष्ट माना है। इसके अलावा 78 फीसदी ने स्थानीय पार्षदों और 76 फीसदी ने सांसदों को भी भ्रष्टाचार में शामिल माना है। इसके बाद टैक्स अधिकारी और धार्मिक नेता भी इसमें शामिल है। दस में से करीब सात लोगों ने जज या मजिस्ट्रेट को भी भ्रष्ट बताया है। *(दै.भा., 08.03.17)*

क्या कहते हैं भारतीय लोग?

लगभग 63 फीसदी भारतीयों ने माना कि सामान्य व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण अंतर ला सकता है तथा 55 फीसदी ने कहा कि वे भ्रष्टाचार पर सबूत देने के लिए दिन भर कोर्ट में खड़े रह सकते हैं।

करीब 38 फीसदी गरीब तबके के लोगों ने कहा कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ी। यह किसी भी आय वर्ग में सबसे ज्यादा है।

डिजिटल पेमेंट से भ्रष्टाचार पर रोक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तेज करने को कहा है। उन्होंने 'मन की बात' कार्यक्रम में बताया कि लोग अब जेब में रुपए रखने की मानसिकता बदल रहे हैं। अब मोबाइल ही उनके लेन-देन का साधन बन रहा है। डिजिटल लेन-देन भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल होगा।

उन्होंने देश के युवाओं से डिजिटल पेमेंट अभियान को आगे बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि वे सफाई अभियान की तरह इस अभियान को भी गांवों तक फैलाएं। उन्होंने बताया कि दो महीनों में डिजिटल पेमेंट पर 10 लाख लोगों को 150 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जा चुका है।

(दै.भा. एवं रा.प., 27.02.17)

'काली' सम्पत्ति पर रहेगी पैनी नजर

भारत में एक नवंबर 2016 से नया और सख्त बेनामी सम्पत्ति एक्ट लागू हो चुका है। इसमें अवैध तरीके के बेनामी ट्रांजेक्शन पर रोक लगाई गई है। कानून में 7 साल की सजा और पेनल्टी का प्रावधान भी है। जिन लोगों ने बेनामी सम्पत्ति खरीद ली है उनके लिए दिक्कत होने वाली है उनका इस प्रॉपर्टी से निकलना मुश्किल होगा। इसके लिए सरकार ने संसद में बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट पास किया है।

बेनामी ट्रांजेक्शन में चल-अचल सम्पत्ति, कोई अधिकार या कानूनी डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। सोना और शेयर भी बेनामी संपत्ति में आ सकते हैं। सरकार के इस कदम से काले-धन पर लगाम लगेगी। जिन लोगों ने आय के अज्ञात स्रोतों से कमाई करके ऐसी प्रापर्टी खरीदी है उनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। *(रा.प., 25.01.17)*

पुराने नोट रखना अब होगा अपराध

सरकार ने अमान्य हो चुके 500 व 1,000 रुपए के पुराने 10 से ज्यादा नोट रखने वालों को दंडित करने के प्रावधान वाले कानून को अधिसूचित कर दिया है। कानून के तहत ऐसे लोगों पर न्यूनतम 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। संसद में इसके लिए निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून 2017 पारित किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 27 फरवरी को इस कानून पर दस्तखत कर दिए हैं।

इस कानून को पारित करने का मकसद बंद किए जा चुके नोटों का इस्तेमाल करते हुए समानांतर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को खत्म करना है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति नोटबंदी की अवधि के दौरान विदेश में था और इस बारे में वह कोई गलत घोषणा करता है, तो उस पर कम से कम 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। *(दै.भा., 02.03.17)*

सूचनाओं का भंडार तैयार करेगा कैग

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने कहा है कि लेखा परिक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हासिल करने में मदद के लिए वह एक अलग ढंग से आंकड़ा संग्रह तैयार कर रहा है। कैग शशिकांत शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया 'हम आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों को देख रहे हैं और उसके लिए एक रिपॉजिटरी तैयार कर रहे हैं, जिसका आगे इस्तेमाल किया जा सकता है।'

शर्मा ने कहा कि उस डेटा आधार के इस्तेमाल से लेखा परीक्षा करने में मदद मिलेगी। हम उस डेटा आधार का इस्तेमाल ऑडिट के लिए करेंगे। उदाहरण के लिए गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी तो उसमें होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का तुरंत पता लग सकेगा।

(न.जु., 10.02.17)

लगेगी घोटालों पर नकेल

राजस्थान में पहली बार घपले रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अब तक किसी घपले की जांच के बाद छोटे अफसर-कर्मचारियों को नोटिस देकर इतिश्री कर लेते थे। लेकिन अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से जुड़ी करीब 10 हजार पंचायतों के 40 हजार गांवों में निर्माण कार्यों की गड़बड़ियों के जिम्मेदार एक दो कर्मचारी नहीं होंगे।

सरकार अब नया प्रवधान लागू करने जा रही है। जिसके तहत उन सभी लोगों को घपले के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा जिनके साइन कार्य की फाइल चलने के पहले दिन से अंतिम दिन तक हुए है । ऐसे सभी लोगों से घपले की राशि की बराबर रिकवरी की जाएगी। फाइल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है। *(दै.भा., 12.02.17)*

भारत में बढ़ा भ्रष्टाचार

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में शामिल 10 में से 4 अर्थात 40 फीसदी भारतीयों ने कहा है कि पिछले एक साल में देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस मामले में हमसे पीछे है। वहां 35 फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ने की बात मानी है। इस मामले में चीन सबसे ऊपर है। वहां 73 फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही है।

संतोष की बात यह है कि करीब 53 फीसदी भारतीयों ने यह भी कहा है कि सरकार भ्रष्टाचार से बेहतर तरीके से निपट रही है। सरकार ने हाल ही में कई अच्छे कदम उठाए हैं जिससे भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी। लोगों का यह भी मानना है कि अब आम लोग भी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आगे आ सकते हैं। *(रा.प., 08.03.17)*

रिश्वतखोरी में भारत एशिया में अव्वल

सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। यहां लोगों को किसी न किसी रूप में रिश्वत देनी ही पड़ती है। यह जानकारी भ्रष्टाचार पर काम करने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है।

इसके मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में रिश्वत के मामले में भारत शीर्ष पर है। रिपोर्ट के अनुसार 69 फीसदी भारतीयों ने इस बात को माना है कि काम करवाने के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देनी पड़ी।

एशिया प्रशांत में 16 देशों के 90 करोड़ लोगों ने इस बात को माना है कि उन्हें कम से कम एक बार रिश्वत देनी ही पड़ी है। जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और आस्ट्रेलिया में घूसखोरी के मामले सबसे कम रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए इस सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि उन्होंने कितनी बार रिश्वत दी, किसे दी और क्यों रिश्वत दी। *(दै.भा. एवं रा.प., 08.03.17)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
चूरू	गोविन्द सिंह	हैड कांस्टेबल, सिधमुख पुलिस थाना, चूरू	10,000	*रा.प., 01.01.17*
ब्यावर	हजारी लाल गुर्जर	पटवारी, सुमेल पटवार मंडल,पाली	31,000	*दै.न., 04.01.17*
जैसलमेर	बागाराम ओड	कनिष्ठ तकनीकी सहायक, सम पंचायत समिति	8,000	*रा.प., 05.01.17*
श्रीगंगानगर	श्यामसुन्दर अरोड़ा मातुराम मेघवाल	लेखाधिकारी, खनिज विभाग कार्यालय कार्यालय सहायक, खनिज विभाग कार्यालय	10,000	*दै.भा. एवं दै.न., 19.01.17*
सीकर	अमरचन्द यादव	कनिष्ठ अभियंता, विद्युत निगम कार्यालय, पाटन	5,000	*रा.प. एवं दै.भा., 20.01.17*
बूंदी	इलफान कुरैशी	प्रवर्तन अधिकारी, रसद अधिकारी कार्यालय,बूंदी	10,000	*दै.न., 21.01.17*
दौसा	गिर्राज प्रसाद	हैड कांस्टेबल, महिला थाना, दौसा	14,000	*दै.न., 07.02.17*
जयपुर	शिव कुमार	कांस्टेबल, शिप्रा पथ थाना, जयपुर	50,000	*रा.प., 09.02.17*
अलवर	बी.एल.यादव	अपर आयकर आयुक्त रेंज (द्वितीय) जयपुर	7,00,000	*रा.प. एवं दै.भा., 17.02.17*
प्रतापगढ़	रामकरण मीणा	कनिष्ठ लेखाकार, स्वरूपगंज ग्राम पंचायत	7,000	*रा.प., 22.02.17*
जोधपुर	किशनलाल गौड़	पटवारी, बिलाड़ा तहसील, चांदेलाल पटवार मण्डल	15,000	*रा.प., 22.02.17*
बूंदी	प्रदीप मीणा रमेश पांडे मनोज त्रिपाठी	जेडीओ, भारतीय संचार निगम लि.(बीएसएनएल) एक्सडीई, भारतीय संचार निगम लि.(बीएसएनएल) एजीएम, भारतीय संचार निगम लि.(बीएसएनएल)	60,000	*दै.भा., 22.02.17*
सवाई माधोपुर	टी.आर. खंगार राजेन्द्र मीणा	मैनेजर, यूको बैंक महाराणा प्रताप कॉलोनी ब्रांच दलाल, अजनोटा निवासी, सवाईमाधोपुर	24,000	*रा.प. एवं दै.न., 24.02.17*
जयपुर	पप्पू राम	कांस्टेबल, बनीपार्क थाना, जयपुर	33,000	*रा.प. एवं दै.न., 08.03.17*
जयपुर	मुकेश नागर प्रवीण शर्मा	ईओ, जोबनेर नगर पालिका, जयपुर मैनेजर, जेसीबी कंपनी	40,000	*रा.प. एवं दै.भा., 11.03.17*
अलवर	जयकांत	एएसआई, नीमराणा थाना, अलवर	30,000	*रा.प., 15.03.17*
नागौर	सीताराम जाट	सहायक परियोजना अधिकारी, साक्षरता कार्यालय	23,000	*दै.न., 18.03.17*
कोटा	महावीर सिंह	थाना प्रभारी, इटावा थाना	20,000	*रा.प. एवं दै.न., 22.03.17*

मध्यम वर्ग को दी आयकर में राहत

केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर की टैक्स स्लेब में बदलाव किया है। वित्तीय वर्ष 1997-98 से लगातार जारी 10, 20 व 30 प्रतिशत के स्लेब को बदल कर 5, 20 और 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे कम आमदनी वाले मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिली है।

स्लेब के मुताबिक 2 लाख 50 हजार रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं है। इसके बाद 2 लाख 50 हजार एक रुपए से 5 लाख रुपए पर अब 10 फीसदी की बजाय 5 फीसदी ही आयकर देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स देय नहीं है तथा 80 साल से अधिक उम्र के करदाता पर 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.02.17)

मिलेगा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा

केंद्र सरकार के बजट से ब्रॉडबैंड व डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। देश में ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में दूरसंचार प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। ऑप्टिकल फाईबर का जाल बिछेगा। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से 1.50 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

पंचायतों के ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ने पर ग्रामीण इलाकों में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार होगा इससे ग्रामीणों के सभी काम गांव में ही आसानी से हो जाएंगे। उन्हें बार-बार शहरों की ओर भागना नहीं पड़ेगा। नोटबन्दी के बाद से डिजिटल भुगतान के तरीकों में भी तेजी से वृद्धि हुई है। बजट में मुद्रारहित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के कई प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश के बजट में इसके लिए डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना की गई है। *(रा.प. एवं दै.न., 02.02.17, 09.03.17)*

बिछेगा सड़कों का जाल

केन्द्र सरकार के बजट के मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तीय वर्ष में 27 हजार करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछेगा। इसमें केन्द्र सरकार के 19 हजार करोड़ रुपए और शेष राशि राज्यों के अंशदान से मिलेगी। राजमार्गों पर 64 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

प्रदेश के बजट के अनुसार राज्य में 2000 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही 800 करोड़ रुपए खर्च कर 5000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण का काम किया जाएगा।

(रा.प. एवं दै.न., 02.02.17, 09.03.17)

ग्रामीण क्षेत्र को दी ज्यादा सौगात

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण विकास पर 25 फीसदी ज्यादा खर्च करने की तैयारी कर इस बार बजट में ग्रामीण क्षेत्र को ज्यादा अहमियत दी है। एक करोड़ गरीब परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को 2019 तक गरीबी से बाहर लाने के लिए बजट में मिशन 'अंत्योदय' शुरू करने का ऐलान किया गया है। पिछले बजट में मनरेगा के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान था जिसे बढ़ा कर 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बजट में घोषणा की है कि प्रदेश में पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को स्मार्ट विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा। इन गांवों में परंपरागत व सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट, वाई-फाई, ई-लाईब्रेरी, खेल मैदान, कचरा प्रबंधन, चारागाहों के विकास जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1198.60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। *(दै.भा. एवं दै.न., 02.02.17, 09.03.17)*

किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान

केन्द्रीय बजट में कृषि ऋण लक्ष्य को एक लाख करोड़ रुपए बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मृदा कार्ड को किसानों के लिए लाभदायक बनाया जाएगा।

प्रदेश के बजट में खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 3156 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की भी कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों के लिए अनुदान 7500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8500 करोड़ रुपए किया गया है।

सीमान्त किसानों के लिए अनुदान 60 से 65 प्रतिशत और सामान्य किसानों का अनुदान 45 से 50 प्रतिशत किया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की जाएगी।

(रा.प. एवं दै.न., 02.02.17, 09.03.17)

योजनाओं का होगा सोश्यल ऑडिट

मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का हर छह माह में एक बार शत-प्रतिशत सामाजिक अंकेक्षण (सोश्यल ऑडिट) होगा। इसके साथ ही वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक हुए सोश्यल ऑडिट अभियान में निकली बकाया राशि की वसूली कर लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जांच दलों को ग्राम सभा की बैठक की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। *(दै.भा., 04.01.17)*

अफसरशाही होगी ज्यादा जवाबदेह

केन्द्र सरकार अब अफसरशाही को पारदर्शी, जवाबदेह और ज्यादा उत्पादक बनाने की कोशिश में जुटी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद कार्मिक व प्रशिक्षण महकमे ने सभी 36 अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों के लिए सालाना कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है।

मोदी सरकार बेहद ईमानदार व काम के प्रति समर्पित अधिकारियों को ही केन्द्र में जिम्मेदारी देगी। अब काम नहीं तो नौकरी नहीं का फार्मूला अपनाया जाएगा। काम में लापरवाही बरतने और गैरजिम्मेदार व्यवहार करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा। *(रा.प., 31.01.17)*

नहीं हो रहा विद्युत उत्पादन क्षमता का उपयोग!

देश में करीब 46 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता तैयार होकर भी रुकी पड़ी है, क्योंकि राज्यों में उन संयंत्रों से बिजली लेने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा का निर्माण नहीं किया गया है। उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए के सदस्य पंकज बत्रा ने बताया कि 46,000 मेगावाट की बिजली क्षमता फंसी पड़ी है।

इसमें 30 हजार मेगावाट तापीय तथा शेष 16 हजार मेगावाट गैस आधारित है। इसका कारण वितरण मोर्चे पर अंतिम छोर तक बिजली पहुंचाने की खराब व्यवस्था है। क्योंकि, राज्यों ने निष्क्रिय बिजली को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाओं का निर्माण नहीं किया।

(न--.नु., 29.03.17)

प्रदेश में बढ़ा छह गुना ऊर्जा उत्पादन

प्रदेश में बिजली उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। विगत 22 वर्ष के दौरान यह मोटे तौर पर छह गुना के करीब हो चुका है। राज्य सरकार की ओर से जारी आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 3049 मेगावाट थी, जो कि 2016-17 के दौरान दिसंबर 2016 तक 17894 मेगावाट से अधिक हो गई है।

इस शताब्दी का पहला साल शुरू होने के दौरान 1999-2000 की समाप्ति तक यह क्षमता 3689 मेगावाट हो गई थी, जो कि 2004-05 तक 5296 मेगावाट तक पहुंची। इसके बाद 2011-12 में इस क्षमता ने 10 हजार मेगावाट का आंकड़ा पार किया और 10308 मेगावाट हो गई। वर्ष 2014-15 में 15907 मेगावाट हो गई । उम्मीद है कि वर्ष 2018-19 में यह 20 हजार मेगावाट तक पहुंच सकती है। *(न.नु., 12.03.17)*

किसानों की बढ़ी बिजली दरें वापस

राज्य सरकार ने किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों पर बढ़ाए गए बिजली टेरिफ को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह राणावत ने इसकी अधिकारिक घोषणा की है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

किसानों को अब पहले की तरह 90 पैसे यूनिट की दर से बिजली के बिल दिए जाएंगे। पिछले साल सितंबर में 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा कर इसे 1.15 पैसे कर दिया गया था इसी तरह अब फ्लेट रेट कनेक्शनों से भी 120 के बजाय 85 रुपए प्रति एचपी से ही बिल वसूला जाएगा। काश्तकारों की ओर से पूर्व में बढ़ी हुई दरों पर जमा कराई गई राशि को आगामी बिलों में समायोजित किया जाएगा।

(दै.भा. एवं रा.प., 19.02.17)

सोलर पावर बाजार में प्रतिस्पर्धा

सनसोर्स एनर्जी के संयुक्त प्रवर्तक आदर्श दास ने कहा है कि भारत में सोलर पावर के संदर्भ में शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धा विश्व के अन्य देशों से मेल नहीं खाती है। उन्होंने कहा कि भारत की कार्यप्रणाली की भिन्नता के कारण अनावश्यक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। सरकारी हस्तक्षेप व नीतियों के चलते कंपनियां अधिकतम वित्तीय जोखिम के साथ व्यवसाय कर रही है।

उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भारत में 100 परियोजनाओं पर काम कर रही है। जिनमें से अधिकांश भूमि पर सोलर पावर संयन्त्रों की स्थापना या रूफटॉप सोलर पावर संयंत्र आधारित है। जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र की संस्थाओं के परिसरों में की गई है।

(न.नु., 23.01.17)

हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े कदम

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि को रेखांकित करते हुए कहा है कि दुनिया ऐसे समय हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है जब जलवायु परिवर्तन विकास के रास्ते में चुनौती बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आधे से अधिक बिजली उत्पादन क्षमता अक्षय ऊर्जा से आ रही है। यूरोप में आंकड़ा 90 प्रतिशत से अधिक है। वैश्विक स्तर पर 80 लाख से अधिक लोग अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। इसका मकसद जलवायु परिवर्तन पर राजनीतिक गतिविधियों में तेजी लाना है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत में सौर ऊर्जा क्षमता 2017-18 में दोगुनी 18 हजार मेगावाट हो जाएगी। *(न.नु., 25.03.17)*

कम हुई सौर परियोजनाओं की लागत

वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा बड़े पैमाने पर सोलर पैनलों की मांग एवं उत्पादन के कारण पिछले आठ साल में सौर परियोजनाएं लगाना दस गुणा सस्ता हो गया है। सौर परियोजना लगाने वाली कंपनी सनसोर्स एनर्जी के सह संस्थापक आदर्श दास ने यह जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में 10 मेगावाट तक की सौर परियोजना का खर्च 10 डॉलर प्रति वाट से घटकर अब एक से सवा डॉलर प्रति वाट रह गया है। इससे सौर प्लांटों से उत्पन्न होने वाली बिजली अब काफी किफायती हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिस जोर-शोर से प्रयास कर रही है, उससे इस क्षेत्र को काफी अच्छे अवसर मिले हैं।

(दै.न., 12.01.17)

बिजली चोरी की होगी मॉनिटरिंग

लगातार बढ़ते वित्तीय घाटे से जूझ रहे प्रदेश के तीनों विद्युत वितरण निगमों में बिजली चोरी और छीजत को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। डिस्कॉम प्रशासन अब बिजली चोरी में शामिल विद्युत निगमों के संदिग्ध कर्मचारियों की भी पहचान करेगा। इस कृत्य में लिप्तता पाए जाने पर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कई बार बिजली चोरी करवाने में विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है।

चिन्हित क्षेत्रों में प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग और विजिलेंस कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी करवाने वाले निगम कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। *(दै.न., 21.01.17)*

प्रदेश में दो तिहाई से ज्यादा डार्क जोन

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने विधानसभा में बताया है कि प्रदेश में 295 ब्लॉक में से 194 डार्क जोन में आते हैं। हर साल 15 मई से 15 जून और 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक ब्लॉकवार सर्वे किया जाता है। जल की विकास दर के आधार पर डार्क जोन की श्रेणी में भी बदलाव किया जाता है।

उन्होंने कहा कि 2016 में हुए सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। राज्य के 295 में से 194 ब्लॉक अति दोहित क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह 10 क्रिटिकल जोन, 38 सेमी क्रिटिकल और 34 नोटिफाईड जोन हैं। प्रदेश में केवल 50 जोन सुरक्षित श्रेणी में आते हैं।

(न.नु., 22.03.17)

गांवों में मिलेगा नल से पेयजल

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने कहा है कि प्रदेश के चार हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में पाइप लाइन से पानी सप्लाई का काम दो वर्ष में चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा तथा एक लाख से कम आबादी के 100 कस्बों की पेयजल योजनाओं के पुनरुद्धार व पुर्नगठन के काम हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में 30-30 हैण्डपंप स्वीकृत किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि अगले दो सालों में प्रदेश की सभी ग्रामीण एवं नगरीय जलप्रदाय योजनाओं की पम्प मशीनरी एवं नलकूपों का एस्को मॉडल पर संघारण किया जाएगा तथा गुणवत्ता से प्रभावित 1483 गांवों में तत्कालिक योजना के तहत आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार गर्मी में कहीं भी पानी की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। *(रा.प. एवं दै.न., 30.03.17)*

जल गुणवत्ता पर खास ध्यान

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे चरण में होने वाले जल संरक्षण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी कार्यों में विस्तृत कार्य योजना के आधार पर ही गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जल संरक्षण कार्यों में तकनीकी खामी होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित की जिम्मेदारी तय कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। *(दै.न., 16.02.17)*

मुहैया कराया जाएगा शुद्ध पेयजल

पेयजल के लिए प्रदेश के बजट में पहली बार योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। जलापूर्ति और सुधार के लिए 6100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। पहले एक साथ इतनी बड़ी राशि बजट में नहीं रखी गई। नई तकनीक के जरिए अब स्वतः ही जलापूर्ति हो सकेगी। यह नवाचार जलापूर्ति में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसके लिए 120 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है।

पानी की चोरी, दुरुपयोग और छीजत को रोकने के लिए कई उपाय किए जाएंगे। 2500 गांवों में शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत 4214 गांवों को शामिल किया जाएगा। अभियान के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(रा.प., दै.भा. एवं दै.न., 09.03.17)

पानी की छीजत पर लेगेगी रोक

जयपुर शहर में प्रतिदिन 47 करोड़ लीटर पानी की सप्लाई की जाती है। इसमें से 15 करोड़ लीटर पानी छीजत में व्यर्थ बह जाता है। लेकिन जापान के तकनीकी सहयोग से जलदाय विभाग ने शहर में पानी की छीजत को 40 प्रतिशत से 15 प्रतिशत पर ला दिया है।

जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव जे.सी. मोहंती ने जानकारी देते हुए कहा कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जायका) के तकनीकी सहयोग से नॉन रेवन्यू वाटर रिडक्शन (एनआरडब्ल्यू) के तहत जयपुर शहर के मानसरोवर, चित्रकूट, आदर्श नगर और बनीपार्क क्षेत्रों का चयन कर वहां खराब मीटरों और जर्जर पाइप लाइनों को बदला गया है और कई तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पानी की छीजत को रोकने के लिए जापान के सहयोग से एनआरडब्ल्यू के तहत पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। *(दै.न., 17.01.17)*

जल संरक्षण मिशन पर फोकस

राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी जिलों में जल संरक्षण मिशन के तहत बजट की 65 फीसदी राशि का उपयोग करेगी। केन्द्रीय भू-जल बोर्ड की 'रिज टू वैली' थीम पर सभी जिलों की वर्ष 2017-18 के लिए डीपीआर बनेगी। जल संरक्षण के तहत अकेले नरेगा विभाग में करीब 100 जल संरक्षण कार्यों का फ्रेमवर्क बनाकर काम होगा।

राज्य सरकार ने जल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन फ्रेमवर्क के तहत वाटरशेड प्रबंधन कार्यों पर फोकस करने का निर्णय लिया है। इस काम के लिए प्रदेशभर में नरेगा, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना समेकित वाटरशेड कार्यक्रम की संयुक्त कवायद की जाएगी। *(दै.न., 27.02.17)*

अब पानी भी हो जाएगा महंगा

प्रदेश में सरकारी पानी की दर एक अप्रेल से 10 फीसदी तक बढ़ जाएगी। जलदाय विभाग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। स्वीकृति की यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता है। क्योंकि 5 नवम्बर, 2015 को जारी नोटिफिकेशन के तहत दर में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वतः हो जाएगी। यह दर पानी के उपयोग पर बढ़ेगी।

देश में राजस्थान पहला प्रदेश है, जहां पर पानी की सप्लाई व कीमत के साथ ही प्रोजेक्ट खर्चे का रिव्यू किए बिना ही टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे माना जा रहा है कि आदेश तो 10 प्रतिशत के हैं, लेकिन पानी 25 प्रतिशत तक महंगा हो जाएगा। जयपुर में नॉन रेवन्यू वाटर के नाम पर विभाग करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, जबकि इसका उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं होगा। *(रा.प., 01.03.17 एवं दै.भा., 30.03.17)*

पति करे सरपंची तो दर्ज होगा मुकदमा

महिला सरपंच की जगह उसका पति या कोई अन्य परिजन कामकाज कर रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। महिला जनप्रतिनिधियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके पतियों और परिजनों की दखलंदाजी पर अंकुश लगाने के लिए कानून बना हुआ है। उन्हें बैठकों में आने से रोका जा सकता है। और जरूरत पड़ने पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।

इस कानून को बने कई साल हो गए, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने इसे गंभीर मानते हुए जिला परिषद को निर्देश दिया है कि ऐसी शिकायतों की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। *(रा.प., 22.02.17)*

खेती से जुड़ी महिलाओं को प्रोत्साहन

सहकारिता और कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को अब केन्द्र व राज्य में प्रोत्साहन दिया जाएगा। देशभर में हर साल 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। करीब आठ लाख सहकारी संस्थाओं में से देश में करीब बीस हजार संस्थाओं को पूर्णतया महिलाएं संचालित कर रही है।

कृषि और कृषि कल्याण योजनाओं में प्रस्तावित राशि का केन्द्र ने तीस प्रतिशत अनुदान महिलाओं के लिए रखा है। इसके साथ ही अब देशभर में बने कृषि विज्ञान केन्द्रों में अब एक महिला वैज्ञानिक की भी अनिवार्य नियुक्ति की जाएगी ताकि खेती से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी महिलाएं बिना किसी संकोच के ले सकें। *(दै.न., 15.03.17)*

गांवों में बनेंगे महिला पंचायत मंच

प्रदेश के सभी गांवों में महिला पंचायत का गठन किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इससे हर महिला की समस्या का समाधान किया जा सकेगा और गांव-गांव तक महिला आयोग की पहुंच होगी।

इसमें महिला पंचायतों से संबंधित प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर ही काउंसलिंग के जरिए निस्तारण किया जा सकेगा। महिला पंचायतों को इसकी रिपोर्ट हर महीने की 30 तारीख तक महिला आयोग को देनी होगी। इससे गांवों में महिला उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी। *(दै.न., 03.01.17)*

संसद में हो महिला आरक्षण

संयुक्त राष्ट्र ने महिला सांसदों की संख्या में भारत को विश्व रैंकिंग में 148 वें स्थान पर रखा है। यूएन विमेन के प्रमुख फूमजील मलमबो-एनगुकूका ने रैंकिंग जारी करते हुए भारतीय संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है, ताकि संसद में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ सके। जारी की गई इस सूची में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों के सदस्यों को शामिल किया गया है।

संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में रवांडा 61.3 प्रतिशत के साथ पहले, बोलिविया 53.1 प्रतिशत के साथ दूसरे और क्यूबा 48.9 प्रतिशत के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत में महिला आरक्षण बिल 20 साल से अटका पड़ा है। *(रा.प., 17.03.17)*

बेटी के जन्म पर अनूठी पहल

सामाजिक संस्थाओं के बूते बेटी बचाने में अपनी अलग पहचान बना चुके श्रीगंगानगर में जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है। एक जनवरी 2017 से जिस परिवार में बेटी का जन्म हो रहा है, उसके परिजन 5-5 पौधे लगा रहे हैं। पौधों के नाम भी अपनी बिटिया के नाम पर किसी ने परी रखा है तो किसी ने पूजा।

जिला प्रशासन के अनुसार सरकारी अस्पताल में जितनी भी बेटियां जन्म लेंगी, उनके परिजन अपनी बेटियों के नाम से पांच-पांच पौधे लगाएंगे। लगाए गए पौधों की देखरेख भी वे खुद करेंगे। *(दै.भा., 05.01.17)*

महिला एवं बाल विकास पर ध्यान

केंद्रीय बजट में महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थ बनाने के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके जरिए जनजातियों, दलितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को उद्योग लगा कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास होंगे। बाल योजनाओं के संचालन पर 1.84 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा।

बालिकाओं और महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केन्द्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता के तहत अब 6000 रुपए मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण व संरक्षण के लिए 307 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।

प्रदेश के बजट में महिलाओं व बालिकाओं से संबंधित कई घोषणाएं सीधे तौर पर ग्रामीण स्तर पर फायदेमंद साबित होंगी। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी घोषणाएं की गई है। महिलाओं में जागृति लाने के लिए चिराली योजना लागू की जाएगी। *(रा.प. एवं दै.न., 09.03.17)*

पांच फीसदी सुधरा लिंगानुपात

केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 (2015-16) के ताजा आंकड़े राजस्थान के लिए सुकून और मुस्कुराहट का सबब बन सकते हैं। जनवरी से जुलाई 2016 के बीच किए गए इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात में पिछले दस साल में 4.7 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यानी 1000 बच्चों पर 887 बच्चियां। जबकि 10 साल पहले यह आंकड़ा 847 था। अर्थात प्रति हजार 40 बच्चियां बढ़ी हैं।

यह ही नहीं वयस्कों में भी महिलाओं का अनुपात सुधरा है। राज्य में अब 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं। साक्षर महिलाओं की संख्या में भी 20.3 फीसदी की वृद्धि हुई है। अभी भी 1000 बच्चों में 15 साल से कम उम्र के 51 बच्चों की मौत हो जाती है और आज भी 36.7 फीसदी बच्चे कम वजन के हैं। *(दै.भा., 06.03.17)*

वित्तीय सेवाएं

नोटबंदी के 'प्रभावों' का होगा हिसाब-किताब

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) नोटबंदी के प्रभावों का ऑडिट करेगा। कैग शशिकांत शर्मा ने कहा है कि उनकी योजना नोटबंदी के वित्तीय प्रभाव से संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से इसके कर राजस्व पर पड़े असर का ऑडिट करने की है। इस ऑडिट में नोटों की छपाई पर खर्च, रिजर्व बैंक के लाभांश भुगतान और बैंकिंग लेन-देन के आंकड़ों को शामिल किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर राजस्व का ऑडिट करने की भी तैयारी की जा रही है। कैग ने सरकार को जीएसटी परिषद के शुरुआती मसौदे में धारा 65 को हटाने पर भी अपना रुख बता दिया है। इसके तहत कैग को जीएसटी के ऑडिट का अधिकार मिलता है। *(रा.प., 27.03.17)*

वित्तीय सुरक्षा पर रहेगा सेबी का जोर

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिए नए साल में निवेशकों के हितों के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। बीते साल नियामक ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए और साझा कोषों तथा आईपीओ के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ाने की दिशा में काम किया।

इसके साथ ही सेबी को उम्मीद है कि बांड बाजारों का दायरा बढ़ाने के लिए उठाए गए कई कदम इच्छित परिणाम देने लगेंगे। नियामक नए साल में इन नए उत्पादों पर विशेष ध्यान देगा ताकि उनकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। इन नए उत्पादकों को निवेशक अनुकूल बनाने के लिए वह सभी सकारात्मक सुझावों का स्वागत कर रहा है। *(न.नु., 03.01.17)*

सड़क सुरक्षा

हादसों में बराबर, जान बचाने में पीछे

सड़क हादसे तो हमारे देश में भी विकसित देशों के बराबर हो रहे हैं लेकिन घायलों की देखभाल हम उतनी तत्परता से नहीं कर पाते, जितनी विकसित देश करते हैं। ऐसे में हमारे यहां हादसों में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इनमें भी युवाओं की संख्या अधिक है। इससे न केवल संबंधित परिवार बुरी तरह चरमराते हैं बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)को भी सीधा नुकसान पहुंच रहा है।

सूचना के अधिकार कानून के तहत सामने आए आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल करीब डेढ़ लाख मौतें हो रही हैं। लगभग 25 लाख घायल अस्पतालों में भर्ती होते हैं और 80-90 लाख लोग मामूली जख्मी हो रहे हैं। प्राथमिक चोट से बचने वाले भी लम्बी अवधि की विकलांगता के शिकार हो रहे हैं। इस स्थिति के चलते देश को 3 फीसदी जीडीपी का नुकसान हो रहा है।

जयपुर स्थित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के न्यूरोसर्जरी विभाग के एक अध्ययन के अनुसार अस्पताल से पूर्व रोगी की देखभाल ठीक ढंग से हो तो परिणाम सुधरेंगे एवं मृत्यु दर में भी कमी आ सकती है। कॉलेज के न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. वी.डी. सिन्हा के अनुसार विकसित एवं विकासशील देशों में घायलों की जान बचाने में अस्पतालों में पूर्व देखभाल का महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है। *(रा.प., 04.02.17)*

दूरसंचार सेवाएं

बढ़ता मोबाइल टावर रेडिएशन...!

मोबाइल टावर से निकलने वाले खतरनाक विद्युत चुंबकीय विकीरणों का खतरा बढ़ रहा है। इस दिशा में सुरक्षा उपायों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि या तो सरकार रेडिएशन की दर कम करे अथवा जनता जागरूकता दिखाए। कोर्ट भी रेडिएशन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि मोबाइल टावर से कोई नुकसान नहीं है तो उन्हें मंत्रियों के घरों के बाहर लगवा दें। इस पर प्रदेश सरकार के प्रमुख मंत्रियों का कहना है कि उनको तो रेडिएशन का कोई नुकसान नहीं नजर आता। चौंकाने वाली बात है कि पांच साल पहले सितंबर 2012 में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने मोबाइल टावर रेडिएशन की दर दस गुना तक कम की थी। सरकार ने विशेषज्ञों के सुझाव को मानते हुए सेहत को प्राथमिकता दी थी। अब चिंता की बात यह है कि मौजूदा 4जी तकनीक के लिए यह दर दोगुनी से भी ज्यादा है। *(रा.प., 02.03.17)*

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार वितरित

'कट्स' द्वारा वर्ष 2002 से हर साल ग्रामीण पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के मकसद से 'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस बार वर्ष 2015 के लिए यह पुरस्कार 'मोटर वाहन (संशोधन) बिल 2016' पर आयोजित पैरवी बैठक के दौरान मुख्य अतिथि बी.एल. सोनी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदान किया गया। उन्होंने डेली न्यूज के पत्रकार गिर्राज शर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं 10 हजार रुपए का चैक प्रदान कर सम्मानित किया।

वर्ष 2015 में उन्होंने चयनित विषय 'स्वच्छ भारत अभियान' पर डेली न्यूज समाचार पत्र में बहुत सी स्टोरियां प्रकाशित कर एवं उनका फोलोअप करते हुए आमजन में जागरूकता लाने का प्रयास किया था।

उपभोक्ता फैसले

उपभोक्ता मंच से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

करीब 19 साल पहले गोविन्द शर्मा ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए जयपुर स्थित सेवायतन अस्पताल में भर्ती कराया था, वहां उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। राष्ट्रीय आयोग के आदेश में बताए गए तथ्यों के अनुसार अस्पताल ने महिला को समय पर खून नहीं चढ़ाया व उसे जनाना अस्पताल रैफर कर दिया।

शर्मा ने अपनी पत्नी और नवजात बच्चों ने अपनी मां को खोया, मामला उपभोक्ता मंच से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जिला उपभोक्ता मंच ने सेवायतन अस्पताल को लापरवाही का दोषी मानते हुए एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए। दोनों ने 2004 में राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की।

आयोग ने राशि दो लाख रुपए कर दी। इसके बाद मामला राष्ट्रीय आयोग में पहुंचा। राष्ट्रीय आयोग ने राशि को 4 लाख 50 हजार रुपए कर दिया। अस्पताल ने राष्ट्रीय आयोग में फिर से गुहार लगाई तो अस्पताल को 10 हजार रुपए और देना पड़ गया। दोनों मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। कोर्ट ने राष्ट्रीय आयोग के फैसले को बरकरार रखते हुए अस्पताल को 50 हजार रुपए अलग से हर्जाना और देने के आदेश दिए।

(रा.प., 09.02.17)

आवश्यक है डिजिटल युग में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

पूरा विश्व तेज गति से डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में हम सभी का दायित्व बनता है कि हर हालत में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण को अहमियत मिले और उनके अधिकारों की रक्षा हो।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में 'कट्स' द्वारा आयोजित 'उपभोक्ता के लिए डिजिटल दुनिया का निर्माण करना' विषयक गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भावना शर्मा, सलाहकार, ट्राई, रीजनल ऑफिस, जयपुर ने यह विचार व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि सेवाप्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। डिजिटल उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए नियमन की जो व्यवस्था होगी वह सहज, सक्रिय, सामर्थ्यवान व कार्यक्षमता युक्त होगी। इसमें बदलाव की तेज गति अभी एक चुनौती है।

कार्यक्रम के प्रारंभ में जॉर्ज चेरियन, निदेशक 'कट्स' ने कहा कि हर साल पूरे विश्व में 15 मार्च का दिन उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। डिजिटल युग में करोड़ों उपभोक्ता रोजाना इंटरनेट एवं मोबाइल के माध्यम से खरीददारी करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। उनके अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के उपाय बहुत जरूरी है।

जैविक राज्य बनाने के लिए 'कट्स' का सिक्किम दौरा

सिक्किम की तरह राजस्थान को भी आने वाले वर्षों में शत-प्रतिशत जैविक राज्य बनाने के लिए 'कट्स' द्वारा जैविक खेती व उसके उपभोग को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना (प्रो-ओर्गेनिक) राजस्थान के छह जिलों में पिछले तीन सालों से संचालित की जा रही है। परियोजना को 2017 में छह जिलों से 10 जिलों में बढ़ाया जा रहा है।

इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए 'कट्स' के परियोजना दल द्वारा 21 व 22 मार्च को सिक्किम राज्य का भ्रमण किया गया। दल ने सिक्किम के कार्यकारी निदेशक डॉ. एस. अनवल्गन से मुलाकात कर कृषि नीतियों के बारे में जानकारी ली। वहां के प्रमुख सचिव खोरलो भूटिया ने बताया कि सिक्किम को शत-प्रतिशत जैविक राज्य बनाने का मिशन 2003 में शुरू हुआ और 2016 में पूरा हुआ।

दल ने सहायक कार्यकारी निदेशक पी.डी. लज्जा और सहायक निदेशक एन. के. प्रधान से भी मुलाकात की और जैविक खेती की विभिन्न तकनीकों की जानकारी ली। दल ने सिक्किम के शिम्खरका गांव में तुलसीराम किसान के खेत में जैविक खेती का जायजा लिया। तुलसीराम 0.29 हेक्टेयर जमीन पर खेती कर सालाना दो लाख रुपए कमा रहा है। दल ने सरकार द्वारा अधिकृत टेमी टी गार्डन में जैविक चाय के उत्पादन की विधि को भी परखा।

स्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, डे.न्यू.: डेलीन्यूज

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।